



प्रदेश की स्थिति पर कांग्रेस हाईकमान का मौन सवालों में

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुक्वू अपने नवनियुक्त मंत्रियों को अभी तक विभागों का आवंटन नहीं कर पाये हैं। बारह दिसम्बर को राजेश धर्माणी और यादवेन्द्र गोमा को मंत्री बनाया गया था। इतने अरसे तक इन्हें विभाग क्यों नहीं दिये जा सके हैं। इसको लेकर अब चर्चाएं उठाना शुरू हो गयी हैं। यह सवाल उठने लग पड़ा है कि क्या कांग्रेस किसी गहरे संकट से गुजर रही है? क्या सरकार को अपरोक्ष में कोई बड़ा खतरा खड़ा होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब मंत्री बना ही दिये गये हैं तो उन्हें विभाग देने में इतना समय लगने का कोई तर्क सामने नहीं आ रहा है। फिर इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान से लेकर प्रदेश तक हर नेता चुप बैठा हुआ है। जबकि मुख्यमंत्री को राय देने के लिये एक दर्जन के करीब सलाहकारों और विशेष कार्यअधिकारियों की टीम मौजूद है। मंत्रियों को विभाग देने में ही देरी नहीं की जा रही है बल्कि पुलिस में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे एक वरिष्ठ अधिकारी को भी पोस्टिंग नहीं दी जा सकी है। यह कुछ ऐसे सवाल बनते जा रहे हैं जिन पर हर आदमी का ध्यान जाना शुरू हो गया है। वैसे ही कांग्रेस को लेकर यह धारणा है कि उसकी सरकारों को कुछ अफसरशाह चलाते हैं। जबकि भाजपा की सरकारों को संघ और कार्यकर्ता चलाते हैं।

आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों में सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं चर्चा और आकलन

मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे पा रहे मंत्रियों को विभाग
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस से सरकार का यू टर्न क्यों

में आती है। हिमाचल सरकार की इस एक वर्ष में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर आने वाले लोकसभा चुनाव जीतने का दावा किया जा सके। क्योंकि कांग्रेस द्वारा चुनावों के दौरान दी गयी गारंटियों को पूरा न कर पाना विपक्षी भाजपा का सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। सरकार की जो वित्तीय स्थिति चल रही है उसके मध्यनजर 31 मार्च तक

महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी पर अमल कर पाना संभव नहीं है। जबकि इन चुनावों में महिला वोटर्स की संख्या 29 लाख के लगभग रहने की संभावना है। इसलिये यह 1500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी ही सारे राजनीतिक गणित को बिगाड़ कर रख देगी। इसी के साथ युवाओं को घोषित रोजगार न देना दूसरा बड़ा मुद्दा है। कठिन वित्तीय स्थिति और प्रदेश में आयी प्राकृतिक आपदा

के आवरण में भी इन मुद्दों को इसलिये नहीं ढका जा सकेगा क्योंकि सरकार ने अपने खर्चों पर कोई लगाम नहीं लगायी है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के दावों पर भी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर यू टर्न ले चुकी है। बल्कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लगने शुरू हो गये हैं। व्यवस्था परिवर्तन के कारण ही प्रशासन

में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हो पाया है। आपदा में केन्द्र द्वारा प्रदेश की उचित सहायता न कर पाने के आरोप को नड्डा ने यह कहकर धो दिया कि आपदा का पैसा अपनी जेब में गया है। केंद्रीय सहायता के जो आंकड़े अब नड्डा ने और पहले अनुराग तथा डा. बिन्दल ने जारी किये हैं उनका कोई सशक्त प्रति उत्तर सरकार और संगठन की ओर से नहीं आ पाया है। इस परिदृश्य में जब राजनीतिक सवाल भी सरकार के अपने ही व्यवहार से खड़ा हो जाये तो क्या उसे विपक्ष को परोस कर देने की संज्ञा नहीं कहा जायेगा। हाईकमान की प्रदेश की स्थिति पर चुप्पी ने इन सवालों को और भी गंभीर बना दिया है।

मुख्य संसदीय सचिवों के प्रकरण ने बढ़ाया नैतिक सवालों का दायरा

शिमला/शैल। मुख्य संसदीय सचिवों के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनको मंत्रियों के समकक्ष मिलने वाली सुविधाओं और मंत्रियों की तर्ज पर काम करने की सुविधाओं पर रोक लगा दी है। यह आदेश आने पर ऐसा लगा था कि शायद अब इनसे कार्यालय और सरकारी कार्यालय की सुविधाएं छिन जायेगी। परन्तु ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि वर्तमान मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां इस आशय के 2006 में बने

✓ कैबिनेट रैंक की नियुक्तियों पर भी उठने लगे सवाल
✓ मुख्य सचेतक और सचेतकों की संभावित नियुक्तियों पर उठे सवाल

एक्ट के तहत हुई है। उस एक्ट में इन सारी सुविधाओं का प्रावधान है और वह एक्ट अभी तक अदालत द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। वैसे इस एक्ट को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है।

लेकिन जब तक एक्ट बना रहेगा तब तक यह लोग अपने पदों पर बने रहेंगे। वैसे यह एक्ट संविधान में मंत्रियों की संख्या को सीमित करने के आशय के हुये संशोधन के मुलतः

उल्लंघना है। इसलिये माना जा रहा है की अन्तिम फैसले में सरकार का 2006 का एक्ट निरस्त होगा ही। लेकिन इस परिदृश्य में यह राजनीतिक सवाल शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल से कश्मीर के विद्यार्थियों ने की भेंट मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं से 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना को साकार करने के लिए अमृत काल में राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र के युवा उस

उपस्थित रहें।

राज्यपाल ने एसोसिएशन द्वारा सांस्कृतिक अध्ययन भ्रमण की पहल पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और हमें एक-दूसरे के सुख-दुःख में शामिल होना चाहिए। यह यात्रा इस

कहा कि इस भ्रमण के दौरान कश्मीर से बड़ी संख्या में छात्राएं हिमाचल आयी हैं, जो कश्मीर में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। वहां पंचायत स्तर पर चुनावों के उपरान्त लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। हिमाचल और जम्मू-कश्मीर पर्यटन की दृष्टि से भी दुनियाभर से लोगों को आकर्षित करते हैं। यह यात्रा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृतियों को जोड़ती है जिससे यह अवसर हम सभी के लिए और भी महत्वपूर्ण एवं समृद्ध अनुभव का प्रतीक बन जाता है। हमारी विविधता में एकरूपता के दर्शन होते हैं और यही हमारी ताकत है। भौगोलिक सीमाओं से परे इस प्रकार के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम एकता की भावना को मजबूत करते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि इस अमृत काल में हर व्यक्ति को विकसित भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए।

इस अवसर पर राज्यपाल ने भ्रमण यात्रा की टीम लीडर राबिया वानी, यात्रा प्रमुख बुरहान भट्ट, परन्तून समुदाय से ग्रुप लीडर जीनत और मीडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन हरियाणा की महासचिव मीनाक्षी को सम्मानित भी किया।

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।

का विवरण मंत्रालय को भेज दिया है। उन्होंने इसके दृष्टिगत शीघ्र मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया।



मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत करवाया कि हिमाचल ने हाल ही की बरसात में आई प्राकृतिक आपदा से संबंधित 'आपदा उपरान्त जरूरतों की आकलन रिपोर्ट' गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उन्होंने केन्द्र से राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद के लिए धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने रियायती हेलीकॉप्टर सेवा योजना के तहत विभिन्न मार्गों को शामिल करने का आग्रह भी किया और केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश ने पहले ही मार्गों

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वाइब्रेट विलेजिज कार्यक्रम के तहत 658.31 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि गृह मंत्रालय ने केवल 3.87 करोड़ रुपये की राशि के 14 कार्यों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उन्होंने शेष धनराशि शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह करते हुए कहा कि इन गांवों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

केन्द्रीय मंत्री ने राज्य को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।



देश की निधि एवं पहचान होते हैं। देश उनके विचारों और सपनों से ही प्रगति करता है।

राज्यपाल ने राजभवन में पंचनाद अनुसंधान संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मीडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और इंडियन मीडिया सेंटर-हरियाणा द्वारा आयोजित सांस्कृतिक अध्ययन टूर 2024 में भाग लेने वाले कश्मीरी विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी

उद्देश्य की पूर्ति करती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा को देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखना चाहिए और इस प्रकार के कार्यक्रमों से यह भावना और सुदृढ़ होती है।

शुक्ल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कश्मीर के विद्यार्थी इस अध्ययन टूर के माध्यम से भाईचारे का संदेश देते हुए जम्मू-कश्मीर के लोगों को यह एहसास करवा रहे हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने

नौणी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फल मक्खी की दो नई प्रजातियों खोजी

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के शोधकर्ताओं द्वारा हिमाचल प्रदेश में फल मक्खियों के लिए किये गये। सर्वेक्षण अध्ययन के दौरान दो नई फल मक्खी (टेफ्रिटिडे) प्रजातियां पायी गयी है।

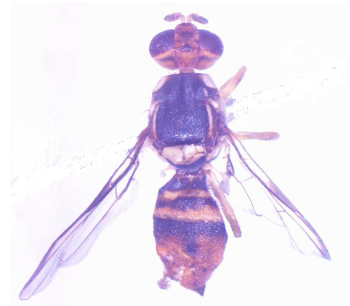
मनीष पाल सिंह के डॉक्टरेट

लक्षण वर्णन और परामर्श के बाद, प्रजातियों को दुनिया के लिए नया घोषित किया गया। इन प्रजाति का नाम बैक्ट्रसैरा प्रभाकरी और टेफ्रिटिस हिमालयी रखा गया। डॉ. मनीष पाल सिंह ने अपने डॉक्टरेट शोध के दौरान, इन नई प्रजातियों का वर्णन किया है। बी. प्रभाकरी मुख्य रूप से मध्य

खरपतवार पर प्रजनन करती हैं।

अन्य उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में राज्य में फल मक्खियों की अधिक विविधता मौजूद है, जैसा कि मनीष द्वारा किये गये शोध कार्य के निष्कर्षों से पता चला है। इस शोध के निष्कर्ष 'जूटाक्सा' जर्नल के नवंबर और दिसम्बर अंक में प्रकाशित हुये हैं, जो न्यूजीलैंड से प्रकाशित होता है। फ्रूट फ्लाई के नमूनों को संदर्भ रिकॉर्ड के लिए सोलन में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के उच्च क्षेत्रीय केंद्र में जमा किया गया है। इन नई प्रजातियों के अलावा डैक्स फ्रलेचरी और उरोफोरा टेरेब्रान भी भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश से रिकॉर्ड किए गए। समूह के रूप में फल मक्खियां अंतर्राष्ट्रीय महत्व और संगरोध महत्व के कीट हैं।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने शोधकर्ताओं को उनकी खोज पर बधाई दी। अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव कुमार चौहान, बागवानी महाविद्यालय के डीन डॉ. मनीष शर्मा ने भी शोधकर्ताओं को उनकी इस खोज पर बधाई दी।



अनुसंधान, जो विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. दिवेन्द्र गुप्ता के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, के शोध कार्य के दौरान यह प्रजातियां पायी गयी। यूनाइटेड किंगडम स्थित फल मक्खी वर्गीकरण विशेषज्ञ डॉ. डेविड लॉरेंस हैनकॉक के

पहाड़ियों-सोलन और शिमला जिलों के कुछ हिस्सों में यह एक औषधीय पौधे, जिसे आमतौर पर डच एग प्लांट कहा जाता है, को संक्रमित करती है। वहीं टी. हिमालयी राज्य की ऊंची और मध्य पहाड़ियों में पायी जाती है, जो सर्कियम फाल्कोनेरी नामक एक कांटेदार

राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी तक बढ़ाई

शिमला/शैल। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य और केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी गई है।

उन्होंने कहा कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी योजनाओं में सत्र के लिए एनएसपी पोर्टल पर छात्रों के पंजीकरण की तिथि 16 जनवरी, 2024 है। प्रथम स्तर के सत्यापन के लिए अंतिम तिथि 30 जनवरी, 2024 और दूसरे स्तर के सत्यापन के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2024 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी संस्थानों, स्कूलों,

कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के प्रमुखों और उच्च शिक्षा उप-निदेशकों से आग्रह किया कि वे एनएसपी के पात्र विद्यार्थियों का ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य या राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे किसी भी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या संबद्धता वाले निजी संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इसके उपरांत किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जायेगा और यह संस्थान प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि सभी पात्र छात्र निर्धारित समय अवधि के भीतर आवेदन करें।

उन्होंने कहा कि नवीनतम अपडेट और आवश्यक जानकारी के लिए

अनाउसमेंट कॉर्नर पर सूचना प्राप्त की जा सकती है और किसी भी तकनीकी पूछताछ के लिए हेल्प डेस्क helpdesk@nsp.gov.in या 0120-6619540 (अवकाश के अतिरिक्त सभी दिनों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) पर संपर्क किया जा सकता है।

शैल समाचार

संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

संयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल व तकसीम के 24,091 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक



अदालतें राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। इनके माध्यम से इंतकाल और तकसीम के हजारों मामलों का निपटारा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 व 5 जनवरी, 2024 को आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 24,091 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें इंतकाल के 20,547 मामले थे। दिसम्बर, 2023 में प्रदेश की राजस्व अदालतों में तकसीम के कुल 1,823 मामले दर्ज किए गए। 3 दिसम्बर, 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक तकसीम के रिकॉर्ड 3,544 मामलों का निपटारा किया गया, जोकि इस दौरान दर्ज मामलों का लगभग 200 प्रतिशत है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भविष्य में भी राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करेगी ताकि प्रदेशवासियों के राजस्व से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।

राजीव गांधी स्टार्टअप योजना चरण-दो में युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार: बाली

शिमला/शैल। पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में युवाओं को सशक्त बनाने व स्वच्छ ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चरण-2 को शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा संचालित करने पर केंद्रित है। यह योजना राज्य के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगी। यह योजना 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगी।

आरएस बाली ने कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना के तहत प्रतिभागियों को तीन बीघा भूमि पर 100 किलोवाट क्षमता की परियोजना स्थापित करने के लिए 25 वर्षों तक लगभग

20,000 रुपये मासिक आय और क्रमशः पांच और दस बीघा भूमि में स्थापित की जाने वाली 200 किलोवाट और 500 किलोवाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 40,000 रुपये व एक लाख प्रतिमाह मासिक आय प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना के तहत, वित्तपोषण में राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत बैंक ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता और राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत इक्विटी प्रदान की जाएगी। सौर ऊर्जा डेवलपर को केवल 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करवानी होगी। यह जमानत राशि 25 वर्षों के उपरान्त डेवलपर को वापिस कर दी जाएगी।

आरएस बाली ने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने तथा ग्रामीण स्तर पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्प है इसके साथ ही लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर समाधान भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

लम्बित राजस्व मामलों का त्वरित निपटारा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ मंडे मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पहली राजस्व लोक अदालत

और 1217 तकसीम के मामले इस वर्ष 4 और 5 जनवरी को आयोजित तीसरी राजस्व लोक अदालत में निपटाये गये। उन्होंने कहा कि अगली राजस्व लोक अदालतें 30 और 31 जनवरी को

दर्ज की गई है। 3 दिसंबर, 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक तकसीम के 1823 नये मामले निपटारे के लिए आए जबकि इस अवधि में तकसीम के 3544 लम्बित मामलों का निपटारा किया गया।

उन्होंने राज्य सरकार के सभी पर्यटन होटलों, हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और विभिन्न विभागों के विश्राम गुहों में क्यूआर कोड आधारित ऑनलाईन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को पर्यटकों को दी जाने वाली सेवाओं में और सुधार सुनिश्चित करने को भी कहा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का पहला चरण शुरू किया है, जिसमें राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ई-टैक्सी परमिट की

पेशकश की गई है। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थापित किए जा रहे ई-चार्जिंग स्टेशनों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके तहत युवा 100 किलोवाट, 200 किलोवाट और 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर सकेंगे। योजना के तहत लाभार्थी को जमानत राशि के रूप में मात्र 10

प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा जबकि 70 प्रतिशत बैंक ऋण की सुविधा सरकार द्वारा दी जाएगी तथा 30 प्रतिशत इक्विटी भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने इस स्टार्ट-अप योजना के तहत किसानों को न्यूनतम आय देने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिये।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विभागों की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें समयबद्ध पूरा करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री की केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री से भेंट

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने ए 320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1376 मीटर से 3010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारिकरण पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण

के संचालन के बारे में भी चर्चा की और पर्यटकों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिमला के लिए तीन, धर्मशाला के लिए चार और कुल्लू के लिए केवल एक उड़ान संचालित की जा रही है, जो क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए अपर्याप्त है।



से अब तक 65000 से अधिक इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें से 11420 इंतकाल के मामले

आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि तकसीम के मामलों की निपटान दर 200 प्रतिशत

मुख्यमंत्री ने देश में अपनी तरह के पहले रिपोर्ट प्रबन्धन पोर्टल और बैठक प्रबन्धन पोर्टल लॉन्च किये

शिमला/शैल। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुये, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल (आरएमपी) और बैठक प्रबंधन पोर्टल (एमएमपी)

पोर्टल में निर्णय लेने के दृष्टिगत वास्तविक समय में डेटा पहुंच की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल में एक-क्लिक पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नोटिस जारी करने

उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना है। एमएमपी बैठक से संबंधित नोटिस और कार्यवाही जारी करने तथा सचिवालय से क्षेत्रीय कार्यालयों तक संचार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक समाधान के रूप में कार्य करेगा। यह पोर्टल बैठक की समयसीमा को सावधानीपूर्वक ट्रैक करते हुये बैठकों के निर्धारण, आयोजन एवं समय पर इन्हें सम्पन्न करने में सहायक होगा तथा बैठक की कारवाही व निर्णयों को रिकॉर्ड भी करेगा और बैठक के उपरान्त इन तक पहुंच भी आसान होगी। यह पोर्टल निर्णय कार्यान्वयन पर कुशल ट्रैकिंग और अनुवर्ती कार्यवाही की सुविधा भी प्रदान करता है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दोनों प्रणालियां सरकार के भीतर महत्वपूर्ण संचार, निर्णय लेने की क्षमता और डेटा प्रबंधन चुनौतियों का सफलतापूर्वक समन्वय करती हैं, जोकि आधुनिक प्रौद्योगिकी के दृष्टिगत शासन में संवेदनशीलता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक उल्लेखनीय पहल है। उन्होंने कहा कि अपने कामकाज में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ता से कार्य कर रही है ताकि लोगों को इनके बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।



लॉन्च किये। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किये गये यह पोर्टल संभवतः देश में अपनी तरह के पहले पोर्टल हैं। इन्हें विकसित करने का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में निर्णय लेने, डेटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल को विभागों, बोर्डों और निगमों में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भेजने और निगरानी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। इन

की सुविधा के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों को स्वचालित रूप से अनुस्मारक और सूचनाएं भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल कार्यालयों को अपने रिपोर्टिंग प्रारूप अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे शासन के विभिन्न स्तरों पर पहुंच सुनिश्चित होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएमपी एक मानकीकृत प्रारूप में स्पष्ट व प्रामाणिक डेटा एकत्र करेगा, जिसका

एम्बुलेंस सेवाओं में सुधार के निर्देश:स्वास्थ्य मंत्री

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन और रखरखाव पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए एम्बुलेंस सेवा

एम्बुलेंस और संबंधित सेवाएं या तो क्रियाशील नहीं हैं या उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता पर मरीजों को आवश्यक सेवाएं

के लोगों द्वारा जन प्रतिनिधियों के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता द्वारा चलाई जा रही 102 व 108 एम्बुलेंस में या तो बुनियादी सुविधाओं, जैसे कि सहायता प्रदाता, ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य चिकित्सा उपकरण का अभाव है या फिर इन बुनियादी सुविधाओं का पर्याप्त रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही इन सेवाओं में सुधार नहीं किया गया और लोगों की असुविधाओं के चलते शिकायतें जारी रहें, तो सेवा प्रदाता के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक प्रियंका वर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी, उप निदेशक (कानूनी), निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, अंकिता वर्मा और कंपनी के हितधारक बैठक में उपस्थित थे।



प्रदाता को अपनी सेवाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से शिकायतें मिली हैं कि कंपनी मानदंडों के अनुसार एम्बुलेंस नहीं चला रही है। यह भी देखा गया है कि

प्रदान करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में किसी भी प्रकार की चूक पर सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश



के लिए शीघ्र कार्यवाही का आग्रह किया, जिसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला मुख्यालयों के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्मित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने संजोली हेलीपोर्ट

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि उड़ान योजना के तहत रक्कड़, पालमपुर, चंबा और रिकांगपिओ के लिए हेलीपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और अगले चरण में अन्य हेलीपोर्ट पर विचार किया जाएगा। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को संजोली हेलीपोर्ट के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य को हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

सराहन में एचपीएआईसी का बिक्री केंद्र खोला जाएगा:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित (एचपीएआईसी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसानों व बागवानों के हितों को विशेष प्राथमिकता

(एचपीएमसी) में विलय करने का निर्णय लिया था। उन्होंने इस निर्णय की पूर्ति के लिए प्रक्रिया को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एचपीएआईसी की सम्पत्ति तथा कर्मचारियों को एचपीएमसी में समायोजित



दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एचपीएआईसी के कुल 19 बिक्री केंद्र हैं और अब रामपुर के सराहन में एचपीएआईसी का बिक्री केंद्र खोला जाएगा।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एचपीएआईसी को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित

किया जाएगा। इससे एचपीएमसी की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तथा बागवानों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्राप्त होंगी।

एचपीएआईसी की प्रबंध निदेशक रीमा कश्यप ने बैठक का संचालन किया तथा बागवानी मंत्री को एचपीएआईसी की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

किसी चीज से डरो मत। तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

बिजली बोर्ड क्यों नहीं दे पाया समय पर वेतन और पेंशन



हिमाचल सरकार का सार्वजनिक उपक्रम राज्य विद्युत बोर्ड अपने कर्मचारियों और पेंशनरों की इस बार समय पर वेतन तथा पेंशन का भुगतान नहीं कर पाया है। ऐसा बोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ है। बोर्ड का वेतन और पेंशन का करीब 190 करोड़ प्रतिमाह का खर्च है जबकि इसका मासिक राजस्व इससे दो गुना है। बिजली बोर्ड से पहले

पथ परिवहन निगम में भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। सरकार कर्मचारियों के पिछले बकाया का भी भुगतान नहीं कर पायी है। महंगाई भत्ता भी प्रशन्नित चल रहा है। इस स्थिति से आम जनता में यह सन्देश गया है की सरकार की आर्थिक सेहत ठीक नहीं है। इस अनचाहे सन्देश से यह आशंका बहुत बलवती हो गयी है की जो सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन ही नहीं दे पा रही है वह जनता को दी हुई गारंटियां कैसे पूरा कर पायेगी। इस परिदृश्य में यह चिन्तन और चिन्ता करना स्वभाविक हो जाता है कि जो उपक्रम राजस्व का अपने में ही बड़ा स्रोत है उनके ही कर्मचारियों को समय पर भुगतान न हो पाने की स्थिति क्यों और कैसे आ खड़ी हुई? स्वभाविक है कि इसके लिये उपक्रम का प्रबन्धन और सरकार की नीतियों के अतिरिक्त और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता।

बिजली बोर्ड के प्रबन्धन को लेकर इसका कर्मचारी संगठन पिछली सरकार के समय से ही इस पर गंभीर सवाल उठा रहा है। लेकिन कर्मचारी संगठन के आरोप पर न तब की सरकार ने कोई ध्यान दिया और न अब की सरकार ने। बल्कि अब तो उसी नेतृत्व को और महिमा मण्डित कर दिया गया है। अब जो नेतृत्व बोर्ड को दिया गया है उसको लेकर भी कर्मचारी संगठन के गंभीर आरोप हैं। यह आरोप रहा है कि बोर्ड नेतृत्व में बोर्ड के हितों के स्थान पर सरकार में बैठे राजनीतिक आकाओं के हितों की ज्यादा रक्षा की। इसलिये आज के संकट के लिये भी कर्मचारी संगठन बोर्ड के प्रबन्धन को ज्यादा जिम्मेदार ठहरा रहा है।

प्रबन्धन की नाकामी के साथ ही यह भी सामने आया है की पिछली सरकार ने जो 125 यूनिट पी बिजली देने का फैसला लिया था उसमें इस घाटे की भरपाई सरकार को करनी थी। लेकिन इस समय मुफ्त बिजली देने के बदले जो पैसा सरकार ने बिजली बोर्ड को देना था उसे यहां सरकार नहीं दे पायी है। इस समय पी बिजली का 170 करोड़ सरकार ने बोर्ड को देना है। यदि इस पैसे का भुगतान सरकार कर देती तो शायद यह संकट न आता। इस परिप्रेक्ष्य में यह सवाल उठता है कि कांग्रेस ने तो चुनावों में 300 यूनिट पी बिजली देने की गारंटी दी है। यदि सरकार 125 यूनिट की भरपाई ही नहीं कर पा रही है तो 300 यूनिट की भरपाई कैसे कर पायेगी? आज मुफ्ती की जितनी गारंटियां सरकार ने चुनावों के दौरान जनता को दे रखी हैं क्या उनकी भरपाई हो पायेगी? इन गारंटियों को पूरा करने के लिये जो खर्च आयेगा वह कहां से पूरा होगा? क्या उसके लिये कर्ज लेने या जनता पर करो का बोझ डालने के अतिरिक्त और कोई विकल्प है? मुफ्ती के लाभार्थियों की संख्या से उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो इस लाभ के दाये से बाहर हैं और मुफ्ती की अपरोक्ष में भरपाई करते हैं। आज जो मुफ्ती की गारंटियां सरकार ने दे रखी हैं क्या उनकी भरपाई पर जो खर्च आयेगा उसका आंकड़ा सरकार जारी करेगी? क्या यह बताया जायेगा कि यह खर्च कहां से आयेगा? इस समय 125 यूनिट पी बिजली देने के बाद वर्तमान सरकार ने भी दो बार बिजली की दरें बढ़ाई हैं और फिर भी समय पर वेतन तथा पेंशन का भुगतान न हो पाना अपने में सरकार की नीतियों पर एक गंभीर सवाल है। बिजली बोर्ड की स्थिति ने इस सवाल को जनता के सामने पूरी नम्रता के साथ रख दिया है की क्या कर्ज लेकर मुफ्ती के वायदे पूरे किए जाने चाहिये?

विकसित भारत संकल्प यात्रा में 10 करोड़ से अधिक लोग शामिल

विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया। मात्र 50 दिनों की अल्प अवधि में 10 करोड़ से अधिक लोग यात्रा में शामिल हो चुके हैं। यह चौका देने वाली संख्या विकसित भारत के साझा दृष्टिकोण के साथ देश भर के लोगों को एकजुट करने में यात्रा के गहरे प्रभाव और बेजोड़ क्षमता का संकेत देती है।

संयोग से, विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ प्रमुख देशों की पूरी आबादी से भी अधिक है। यात्रा को मिला व्यापक समर्थन विकसित भारत के निर्माण के प्रति नागरिकों के दृढ़ समर्पण को दर्शाता है।

अरुणाचल प्रदेश के मुकुट रत्न, अंजाव से लेकर गुजरात के पश्चिमी तट पर देवभूमि द्वारका तक, लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर चढ़ाई और अंडमान के फिरोजा तटों की शोभा बढ़ाने तक, विकसित भारत संकल्प

यात्रा ने देश के सुदूरवर्ती इलाकों में समुदायों तक पहुंचकर सभी क्षेत्रों को गले लगाया है। इस यात्रा ने कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और लोगों को इनका सीधा लाभ देना सुनिश्चित कर, भारत की विशालता में उत्साह और आशा की एक चिंगारी पैदा की है।

15 नवम्बर, 2023 को इसकी शुरुआत के बाद से, 7.5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने '2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता का - संकल्प' - लिया - कुछ ही हफ्तों में नागरिकों के बीच यात्रा तेजी से प्रभाव देखने को मिला।

यात्रा का प्रभाव गहरा और जीवन बदलने वाला है। 1.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किये गये हैं और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य शिविरों में 2.2 करोड़ से अधिक नागरिकों की जांच की गई है। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हुए 7.5 लाख से अधिक

लाभार्थियों ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाया है। यात्रा के दौरान 33 लाख से अधिक नए पीएम किसान लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। 87000 से अधिक ड्रोन प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं जो किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ एक मार्च से कहीं अधिक है (यह कार्य करने का एक शक्तिशाली आह्वान है जिसकी प्रतिध्वनि देश भर में गूंज रही है। बदलाव लाने के लिए आज किए गए प्रयास, एक समृद्ध भविष्य का वादा करते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के करीब लाने का साहसिक संकल्प लेना है। यह इस बात पर जोर देता है कि विकसित भारत की ओर यात्रा एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है बल्कि सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने का एक सामूहिक प्रयास है।

99 प्रतिशत से अधिक मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खाते में किया जा रहा है

मंत्रालय द्वारा यह नोट किया गया है कि प्रेस के कुछ वर्गों ने यह उद्धृत किया है कि 'सरकार को देश के सबसे कमजोर नागरिकों को उनके सामाजिक कल्याण लाभों से वंचित करने, लंबित वेतन भुगतान जारी करने, उपस्थिति पत्रक और सामाजिक ऑडिट लागू करने के साथ-साथ अपनी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक हथियार के रूप में प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से आधार का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए।'

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक मांग आधारित योजना है और विभिन्न आर्थिक कारकों से प्रभावित है। देश में पंजीकृत जॉब कार्डों की कुल संख्या 14.32 करोड़ है, जिनमें से केवल 9.77 करोड़ (68.22 प्रतिशत) सक्रिय जॉब कार्ड हैं। कुल 25.25 करोड़ श्रमिकों में से केवल 14.32 करोड़ (56.83 प्रतिशत) सक्रिय श्रमिक हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी/रिमोट सेंसिंग से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रौद्योगिकियों तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों के उपयोग ने योजना के कार्यान्वयन में परिवर्तन लाया है।

इस योजना के तहत, कार्यस्थल पर काम करने वाले लाभार्थियों की वास्तविक समय उपस्थिति अब राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएसएस) ऐप की मदद से दर्ज की जा रही है और लाभार्थियों के साथ-साथ कोई भी नागरिक श्रमिकों की पहचान सत्यापित कर सकता है। इसी प्रकार, रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग सार्वजनिक निरीक्षण के लिए परिसंपत्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली वित्त वर्ष 2016-17 में शुरू की गई थी ताकि वेतन भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जा सके। वर्तमान में 99 प्रतिशत से अधिक मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खाते में किया जा रहा है। योजना के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सर्वोत्तम प्रथाएं नई हैं।

लाभार्थियों को आधार से जोड़ना

एक निर्बाध प्रक्रिया है जो वास्तविक लाभार्थियों का सत्यापन करते समय लाभार्थियों के डुप्लीकेशन से बचने के लिए जारी रहती है, जिससे केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ मिलता है। कुल 14.32 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 14.08 करोड़ (98.31 प्रतिशत) सक्रिय श्रमिकों ने आधार लिंकेज पूरा कर लिया है। इस आधार जोड़ के साथ, कुल 13.76 करोड़ आधार प्रमाणित हो गये हैं और 87.52 प्रतिशत सक्रिय कर्मचारी अब एबीपीएस यानी आधार आधारित भुगतान प्रणाली के लिए पात्र हैं।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा से पता चलता है कि जहां आधार के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे जमा किया जाता है, वहां सफलता दर 99.55 प्रतिशत या उससे अधिक है। खाता आधारित भुगतान के मामले में सफलता दर लगभग 98 प्रतिशत है।

पब्लिक रिसर्च एंड एडवोकेसी ग्रुप - लिबटेक द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर में इसका हवाला दिया गया है और तदनुसार कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि एबीपीएस पर बैंक खाते से भुगतान का कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है और एबीपीएस के मामले में यह केवल 3 प्रतिशत है। इसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि महात्मा गांधी एनआरएजीएस के पैमाने को देखते हुए, यह 3 प्रतिशत लाभ भी एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। इस लिबटेक अध्ययन ने पुष्टि की है कि एबीपीएस प्रक्रिया बेहतर प्रवर्तन का पक्ष लेती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक पारदर्शिता आती है।

किसी परिवार का जॉब कार्ड केवल कुछ परिस्थितियों में ही रद्द किया जा सकता है, लेकिन आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली के कारण नहीं। जॉब कार्ड को अपडेट करना या रद्द करना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। यदि जॉब कार्ड नकली (गलत जॉब कार्ड) है, यदि यह डुप्लिकेट जॉब कार्ड है या यदि परिवार काम करने का इच्छुक नहीं है या

यदि परिवार ग्राम पंचायत क्षेत्र से स्थायी रूप से पलायन कर चुका है या यदि जॉब कार्ड एक ही व्यक्ति का है और अब वह व्यक्ति मर चुका है तो ऐसे मामलों में ही जॉब कार्ड रद्द किया जाएगा, यह निर्धारित किया जा सकता है। अप्रैल, 2022 से, राज्यों ने उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए लगभग 2.85 करोड़ जॉब कार्ड रद्द कर दिए हैं। आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली और इसके लाभों पर विभिन्न मंचों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, बैंकों, एनपीसीआई, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सहित नागरिक समाज संगठनों से परामर्श किया गया है।

काम की निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग, आधार डेटाबेस के माध्यम से रियल टाइम अटेंडेंस ऐप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएसएस), फेस ऑथेंटिकेशन के लिए ड्रोन के उपयोग के प्रारंभिक परीक्षण से पहले एक विशिष्ट पायलट अध्ययन के साथ-साथ परामर्श भी किया गया है। रोजगार के लिए मजदूरी पर जाने वाले लाभार्थियों को भुगतान आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि कुल पंजीकृत श्रमिकों में से 34.8 प्रतिशत और सक्रिय श्रमिकों में से 12.7 प्रतिशत अभी भी आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली के लिए अयोग्य हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली केवल तभी लागू होती है जब जब कोई पंजीकृत लाभार्थी मजदूरी रोजगार के लिए आता है। भारत सरकार ने लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एबीपीएस के माध्यम से अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने का निर्णय लिया है, भले ही लाभार्थी का बैंक खाता बार-बार बदला गया हो। यदि राज्य के किसी जिले की ग्राम पंचायत को तकनीकी समस्या या आधार से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है, तो भारत सरकार समस्या का समाधान होने तक मामले-दर-मामले आधार पर एबीपीएस छूट पर विचार कर सकती है।

आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हुए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए नए भारत में अधिक गुरुकुलों की आवश्यकता है: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

शिमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आह्वान किया है कि देश में न केवल आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाये, बल्कि भारत की नैतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए देश में और अधिक गुरुकुल स्थापित किए जाने चाहिए। 06 जनवरी, 2024 को हरिद्वार, उत्तराखंड में स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में 'गुरुकुलम एवं आचार्यकुलम' की आधारशिला रखने के बाद, राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब विदेशी संस्कृति के अनुकरण के कारण नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, युवाओं को नैतिक मूल्यों के समावेश के साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुकुलों को यह दायित्व निभाने के लिए आगे आना चाहिए।

लगभग 1,000-1,500 वर्ष पूर्व भारत वर्ष में कई बड़े विश्वविद्यालय थे, जिनमें गुरुकुल परंपरा प्रचलित थी। उसके बाद, देश ने विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा उस व्यवस्था को लगभग नष्ट होते हुए देखा। बदले में, उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो हमारे युवाओं को देश की सांस्कृतिक भावना के अनुरूप शिक्षा प्रदान नहीं करती थी। भारतीय संस्कृति को कमतर आंका गया गया। इस भावना ने न केवल हमें राजनीतिक

रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि उस दौरान, स्वामी दर्शनानंद जी ने इस गुरुकुल की स्थापना की, जो तत्कालीन समय से हमारी युवा पीढ़ियों को ज्ञान और संस्कृति के माध्यम से दीप्तिमान कर रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए, राजनाथ सिंह ने प्राथमिक शिक्षा से ही युवाओं के मन में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि 'देश भर के कई शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। यह प्रक्रिया लंबी है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता। उन्होंने कहा कि गुरुकुल इस लंबी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।'

रक्षा मंत्री ने कहा कि गुरुकुल यह आभास व्यक्त करते हैं कि वे केवल शिक्षा की प्राचीन पद्धतियों का पालन करते हैं, लेकिन आज के समय में वे प्रगति कर चुके हैं और आधुनिक हो गये हैं। उन्होंने गुरुकुलों से आज के निरंतर विकसित हो रहे समय के साथ तारतम्य बिठाते हुए पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम

प्रौद्योगिकी जैसी उभरती और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अग्रसर होने का आह्वान किया। 'ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित करें जो देश को इस क्षेत्र में अग्रणी बनायें। उन्होंने कहा कि गुरुकुलों को अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए, आने वाले समय में वे एक बार फिर देश और उसकी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करें और भारत की नई पहचान बनें।

राजनाथ सिंह ने देश में सांस्कृतिक विकास में गुरुकुलों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 'काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकालेश्वर धाम से राम मंदिर तक बुनियादी ढांचागत विकास से पता चलता है कि सरकार हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण और उसके उत्थान की दिशा में कार्यरत है। यह विचार सांस्कृतिक संरक्षण से भी आगे जाता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस महान देश की संस्कृति पर गर्व कर सकें। उन्होंने कहा कि गुरुकुल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।'

रक्षा मंत्री ने योग के बारे में विशेष उल्लेख किया और बताया कि कैसे इसके हितकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व ने प्राचीन भारतीय पद्धति का अनुसरण किया है। 'भारत वसुधैव कुटुंबकम (विश्व एक परिवार) की अवधारणा का पालन करता है। हमारे ज्ञान का विशाल भंडार पूरी दुनिया को समर्पित है। अब 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि योग की इस प्रथा

को, कभी केवल भारत तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन अब इसे विश्व स्तर पर लोगों ने स्वीकार किया है, अब योग प्रणाली पूरे विश्व के लोगों के दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।' भारतीय साहित्य में संस्कृत के महत्वपूर्ण स्थान पर प्रकाश डालते हुए, राजनाथ सिंह ने प्राचीन भारतीय भाषा को उसी तरह बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया जिस प्रकार से योग को लोगों के लिए सुलभ बनाया गया था।

सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सहायक और सशक्त वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध

शिमला। आवसन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रेहड़ी पटरी वालों के बीच विवादों और झगड़ों के समाधान के लिए स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 के तहत सुदृढ़ शिकायत निवारण समितियों की स्थापना और रखरखाव के महत्व पर जोर दिया है। कल 'स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शिकायत निवारण समिति (जीआरसी)' पर एक सेमिनार का उद्घाटन करते हुये उन्होंने शासन, जोखिम और अनुपालन के लिए जीआरसी का गठन करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बधाई दी और शेष राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से जल्द से जल्द समिति के गठन में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों ने लंबे समय से शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मंत्रालय देश भर में रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक सहायक और सशक्त माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने 04 जनवरी, 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 'स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शिकायत निवारण समिति (जीआरसी)' पर सेमिनार आयोजित किया। इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जागरूक करना था। सुदृढ़ जीआरसी के महत्व और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के भीतर कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए जीआरसी सदस्यों सहित प्रमुख हितधारकों को एक मंच प्रदान किया गया। सेमिनार में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, जीआरसी के सदस्य और अन्य विशेषज्ञ और नागरिक समाज संगठनों के साझेदारों ने भाग लिया। इस आयोजन ने राज्य के अधिकारियों और जीआरसी सदस्यों के बीच क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, ताकि रेहड़ी पटरी वालों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रतिभागियों को उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान

करने का भी अवसर मिला, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत प्रभावी जीआरसी का सफलतापूर्वक गठन और प्रबंधन किया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेमिनार के दौरान दो वेबसाइट, पीएआईएसए पोर्टल डैशबोर्ड और पीएम स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू किए। ये पोर्टल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए मिशन और योजना पर वास्तविक समय पर कार्य की प्रगति का ब्योरा अपडेट करेंगे।

कार्यक्रम में सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 और जीआरसी पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें इसके कानूनी ढांचे तथा निहितार्थों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। 'स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना' विषय पर एक पैनल चर्चा हुई। इसमें भाग लेने वाले विशेषज्ञों ने स्ट्रीट वेंडर्स के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और प्रभावी समाधान प्रस्तावित करने पर बल दिया। इसके लिए 4,342 टाउन वेंडिंग समितियों का गठन, 13,403 वेंडिंग जोन का सीमांकन, 1,350 वेंडिंग बाजारों का निर्माण और 38.06 लाख वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 विक्रेताओं को मनमाने निष्कासन से बचाता है, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है और व्यवसायिक शहरी स्थानों में योगदान देता है।

मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उन्हें कोविड-19 महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए 01 जून, 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। 57.83 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को पहली अवधि, 16.23 लाख से अधिक को दूसरी अवधि और 2.16 लाख से अधिक को तीसरी अवधि का ऋण प्रदान किया गया है। यह 43 महीनों के अंतराल में हासिल किया गया है, जबकि इस दौरान देश में महामारी की तीन लहरें आयी थीं।

दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने में प्रदेश सरकार की नवोन्मेषी पहल राज्य में एक वर्ष में 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित

शिमला। पशु पालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रदेश में ये रोजगार का साधन और महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। डेयरी क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हिमाचल को देश का समृद्ध राज्य बनाने की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय दुग्ध उत्पादकों की खुशहाली और समृद्धि की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और दुग्ध उत्पादन में पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंग ने इस वर्ष राज्य में 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट (एमसीयू) में स्थापित किये हैं। प्रदेश में 455 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट कार्यशील हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 106 बल्क मिल्क कूलर लगाये जा चुके हैं। दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए सोसायटी स्तर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 35 केन मीटर कूलर प्रदान किए गए हैं।

प्रदेश सरकार राज्य में सहकार को बढ़ावा प्रदान कर ग्रामीणों की उन्नति के द्वार खोल रही है। डेयरी क्षेत्र के विकास में सहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर समितियों को संगठित किया जा रहा है। वर्तमान में इन समितियों की संख्या बढ़कर 1,107 हो गई है।

प्रदेश में श्वेत क्रांति की शुरुआत कर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से महत्वाकांक्षी हिम गंगा योजना आरम्भ की है। योजना के तहत प्रथम चरण में लोगों को जागरूक करने के लिए समितियां गठित की गई हैं। जिला हमीरपुर और कांगड़ा में 201 नई दुग्ध सहकारी सोसायटियों का गठन किया गया है। जिला हमीरपुर में 11 महिला सोसायटियां और जिला कांगड़ा में 8 महिला सोसायटियां गठित की गई हैं जो प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को इंगित करती हैं। हमीरपुर जिला में 4 सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है। इन दुग्ध सहकारी सोसायटियों के माध्यम से 4064 किसानों को जोड़ा गया है। डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। डेयरी फार्मिंग से जुड़े किसानों को

लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिला कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजेरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंग ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए पंजीरी तैयार करने की गतिविधियों में विविधता लायी है। दुग्ध प्रसंग द्वारा फोर्टीफाइड पंजीरी, फोर्टीफाइड बेकरी बिस्कुट, फोर्टीफाइड गेहूं सेवियां और होल मिल्क पाऊडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार की यह पहल प्रदेश के नौनिहालों के स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की नींव रख रही है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में डेयरी क्षेत्र सहकारी मॉडल, पोषण, पशुधन देखभाल, रोजगार, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सिरमौर जिला के 1388 आपदा प्रभावित परिवारों के 'पुनर्वास' को 9.88 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बरसात के दौरान आयी आपदा से जिला सिरमौर के 1388 प्रभावित परिवारों के 'पुनर्वास'

और केंद्र सरकार से बात हुई है। इसके साथ ही किशाऊ जल विद्युत परियोजना में वाटर कम्पोजेंट आधार पर पावर कम्पोजेंट में 90:10 केंद्र तथा राज्य

से अधिक लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत 20 लाख रुपए तक एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजना लाने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक की मांग पर मुख्य सड़क बुरमपापरी, पालियां भोगपुर सिम्बलवाला से गुम्ती से बस स्टैंड गुम्ती तक सभी चार बस्तियों के लिए सड़क निर्माण तथा भोगपुर सिम्बलवाला सड़क पर रून नदी पर डबल लेन पुल के निर्माण की भी घोषणा की। इस सड़क से क्षेत्र की तीन पंचायतों की लगभग 9000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने खाजूना बिक्रम बाग सुकेती कालाअंब सड़क पर पथराला का खाला पर डबल लेन पुल निर्मित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की चार पंचायतों के लगभग 13000 लोगों को सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने बनोग धार क्यारी से सब्जी मंडी कांशीवाला सड़क बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे सड़क से नाहन शहर, नाहन पंचायत, सेन की सेर तथा अंबवाला सैनवाना क्षेत्र के लगभग 86000 लोग लाभान्वित होंगे।

महिला मंडलों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के मनाली में पांच दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल का शुभारम्भ किया।

करने की भी घोषणा की।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्षेत्र की संस्कृति को प्रमुखता से प्रदर्शित करने और इसमें महिलाओं



के लिये 9.88 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त नाहन में वितरित की। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 66 घरों के लिए 3-3 लाख रुपए की राशि के रूप में 1.98 करोड़ रुपए की पहली किस्त, 718 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 6.37 करोड़, 292 गौशालाओं को नुकसान पर 1.15 करोड़ रुपए तथा अन्य प्रभावित परिवारों को 38 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई।

इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेणुका डैम का कार्य जल्द ही शुरू होगा, जिस पर दिल्ली सरकार

सरकार को फंड करने अथवा राज्य के हिस्से में सभी पावर कम्पोजेंट में 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध भी केंद्र से किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धौलासिद्ध, लुहरी तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली की रॉयल्टी बढ़ाने पर भी उन्होंने केंद्र सरकार से बात की है ताकि प्रदेश के लिए अधिक से अधिक राजस्व जुटाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जन सेवा को ध्यान पर रखकर नीतियां बना रही है ताकि अधिक



उन्होंने ऐतिहासिक हिडिम्बा मंदिर में पूजा-अर्चना करने के उपरान्त परिधि गृह मनाली से कार्निवल परेड को झंडी दिखा कर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के 250 से अधिक महिला मंडल और सांस्कृतिक दल परेड में शामिल हुए। सांस्कृतिक दलों ने सामाजिक सन्देश, संस्कृति और परम्पराओं पर आधारित आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनु रंगशाला में दीप प्रज्ज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। विंटर कार्निवल में विभिन्न राज्यों के 25 प्रतिभागी समूह भाग ले रहे हैं। उन्होंने महिला मंडलों, विभागों और संस्थाओं द्वारा निकाली गई झाकियों में गहरी रुचि दिखाई।

इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला मंडलों को प्रदान की जाने वाली 'प्रोत्साहन राशि' को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मनाली में 15 मील के पास नए पुल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोहतांग-मनालसू पर्यटन होटल का जीर्णोद्धार किया जाएगा और विद्युत बोर्ड की भूमि पर पार्किंग बनाने की संभावना तलाशने के लिए भी सर्वेक्षण किया जायेगा। इसके अलावा उन्होंने निकट भविष्य में मनाली में स्कीइंग कार्यक्रम आयोजित

की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विंटर कार्निवल मनाली की सराहना की। उन्होंने आपदा राहत और बचाव कार्यों में मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बागवानों के उत्पादों को समय पर बाजार तक पहुंचाना सुनिश्चित किया है, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान से बचाया जा सका है। उन्होंने आपदाओं से सीख लेने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिला प्रवास के पहले दिन जिला के लिए 198 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किये हैं।

विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने मनाली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उदार धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मनाली बाईपास के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आइस स्केटिंग रिक परियोजना की शुरुआत भी की जा रही है।

इस वर्ष मनाली में विंटर कार्निवल के दौरान विंटर क्वीन, वॉयस ऑफ कार्निवल और लेफ्ट और राइट बैंक की महिलाओं की महानाटी जैसे कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाएंगे।

इस अवसर पर उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

अरनी विवि तथा स्थानीय प्रशासन के बीच उठे मामले की जांच के आदेश

शिमला/शैल। अरनी विश्वविद्यालय, इंदौरा के प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के बीच उठे मामले तथा मीडिया रिपोर्ट्स का जिला प्रशासन द्वारा कड़ा संज्ञान लिया गया है इस बाबत उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने अतिरिक्त उपायुक्त को तथ्यों की जांच करने तथा संबंधित लोगों का पक्ष सुनने के उपरान्त तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं।

उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि विवि प्रबंधन द्वारा कुछ कर्मचारियों से सेवाएं कथित तौर पर समाप्त कर दी गई थी। जिसके संबंध में एसडीएम इंदौरा मामले पर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया था। एसडीएम से प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया कि जो कर्मचारी 28-12-2023 से शांतिपूर्ण हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने अब 03-01-2024 को अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है।

जबकि, कई मीडिया संस्थानों में समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आयी हैं कि पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रतिकूल

भूमिका निभाई गई है। इससे पहले भी विश्वविद्यालय के उच्च प्रबंधन ने स्थानीय प्रशासन पर धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके संबंध में एसडीएम इंदौरा से रिपोर्ट मांगी गई थी।

उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि नवीनतम मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर, स्थानीय प्रशासन के खिलाफ ऐसे आरोपों की सत्यता स्थापित करना जरूरी है, जैसा कि स्थानीय मीडिया के साथ-साथ अरनी विश्वविद्यालय के प्रबंधन की दलीलों में भी सामने आ रहा है। इसके अलावा, उन तथ्यों की जांच करना महत्वपूर्ण है जिनके कारण ऐसे आरोप लगे हैं और पूरे प्रकरण में स्थानीय प्रशासन की भूमिका को लेकर भी गहनता से जांच की जाएगी। इस के लिए अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जसल को गहन जांच करने तथा सभी संबंधित पक्षों को सुनने के उपरान्त तीन सप्ताह के भीतर तथ्योन्वेषी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रयासरत हिमाचल पुलिस

शिमला/शैल। पिछले एक साल में हिमाचल पुलिस ने अपराधिक घटनाओं का पता लगाने तथा अपराधों की रोकथाम करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन विभाग, आयकर विभाग, राजस्व निदेशालय व वित्तीय अन्वेषण यूनिट जैसी संस्थाओं के साथ सूचना का आदान प्रदान एवं अन्य सहयोग किया जा रहा है।

पिछले वर्ष 2023 में कुल 19 हजार 987 अभियोग पंजीकृत किए गये हैं। इस अवधि में वर्ष 2022 की समरूप अवधि में मादक पदार्थ अधिनियम में पंजीकृत अभियोगों में 42 प्रतिशत की वृद्धि व बन अधिनियम में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध-2022 (Crime in India-2022) के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों में 31.5 प्रतिशत की कमी आयी है।

इसी तरह Crime in India-2022 के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 03 प्रतिशत की कमी आयी है।

वर्ष 2023 के दौरान मादक पदार्थ अधिनियम के 2146 अभियोग दर्ज किये गये हैं जबकि वर्ष 2022 के दौरान 1516 अभियोग दर्ज किये गये थे। पिछले वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत अभियोग अधिक दर्ज किये गये हैं।

वर्ष 2023 में वर्ष 2022 की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक हैरोइन व दोगुनी मात्रा में ज्यादा स्मैक व चूरा पोस्ट बरामद किया गया है।

नशे की तस्करी में सलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी में भी 40

प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ-साथ इन अभियोगों में मादक पदार्थों की जब्ती में भी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

नशातस्करों की गिरफ्तारी के साथ-साथ उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 13.51 करोड़ रुपये की सम्पत्ति की कुर्की (property attachments) के 23 मामले सक्षम कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं।

मादक पदार्थ अधिनियम के 07 अभियोग ई.डी.को कार्यवाही के लिये भेजे गये हैं जिनमें 40 करोड़ रुपये की सम्पत्ति शामिल है।

इस वर्ष 170 मामलों में मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत जब्त की गयी case property को नियमानुसार नष्ट किया गया है।

वर्ष 2023 के दौरान देवभूमि से नशे के उन्मूलन की लड़ाई में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा प्रधाव के रूप में राज्य के युवाओं एवं अन्य हितधारकों (stakeholders) जैसे कि न्यायाधीश, आबकारी विभाग, अभियोजन/विधि विभाग, पत्रकार इत्यादि के सहयोग से प्रदेश में युवाओं के लिए एक विभिन्न चरणों में विचार-मंथन/जागरूकता शिविर आयोजित किया गया जिसमें नशे पर पूर्ण लगाम लगाने हेतु रणनीतियों पर विशेष रूप से चर्चा की गयी।

वर्ष 2023 में पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसका विषय 'नशा छुड़ाओ-पर्यावरण बचाओ, देवभूमि को सुरक्षित बनाओ' था।

बैठक में विद्यार्थियों को नशा न करने के लिये शपथ दिलाई गयी। दिनांक 25.06.2023 को शिमला में half marathon का आयोजन किया गया जिसके विषय था 'Run for

Drug-Free, Safe & Green Himachal'.

दिनांक 11-10-2023 को प्रदेश पुलिस ने PIT ND&PS अधिनियम 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के लिये पहली बार एक स्थायी आदेश जारी किया है।

वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं के 2597 अभियोग पंजीकृत हुये हैं, जबकि वर्ष 2022 में 2255 अभियोग पंजीकृत हुये थे। वर्ष 2022 की तुलना में इस वर्ष 13 प्रतिशत कम मामले पंजीकृत हुये हैं।

इसी तरह सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या में 14 प्रतिशत व घायलों की संख्या में 12 प्रतिशत की कमी आयी है।

विश्व बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा में अपनाई जा रही नितियों के प्रयासों की सराहना की है।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम प्रदेश में HPRIDCL विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में बचाव, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं, सड़क सुरक्षा प्रवर्तन को सुदृढ़ करना, पुलिस, होम गार्ड और एस.डी.आर.एफ. की क्षमता निर्माण, राज्य में यातायात व्यवस्था का पुनर्गठन आदि शामिल है। परियोजना के प्रथम चरण में शिमला और पुलिस जिला नूरपुर और पालमपुर-शिला (धर्मशाला) के लिये Patrolling vehicle, इंटरसेप्टर वाहन, crane and AI cameras और उन्नत उपकरण के लिए 47.79 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। प्रथम चरण के पूरा होने के बाद जिला मंडी और कांगड़ा को कवर किया जायेगा।

विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा भारत:धनखड़ नड्डा ने गिनाई केंद्र की उपलब्धियां एक से श्रेष्ठ छात्रों के समग्र विकास के लिए अनूठी पहल:अनुराग सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हिमाचल से उन्हें सदैव लगाव रहा है और यहां की सरलता और संस्कृति से वह काफी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि यहां वह बार-बार आते रहेंगे यह उनका वायदा नहीं बल्कि संकल्प है।

उपराष्ट्रपति हमीरपुर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में 'एक से श्रेष्ठ' संस्था के 500वें सेंटर के शुभारम्भ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी डॉ.सुदेश धनखड़ भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गये हैं और जल्द ही हम तीसरे पायदान पर होंगे। उन्होंने कहा कि देश में

इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम सामाजिक सरोकार और मानवीय मूल्यों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एक सांसद को कोई न कोई कार्य सेवा के रूप में लेना चाहिए। उसी तरह अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र में अनेक सेवा के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक प्रकल्प सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि एक से श्रेष्ठ के पांच केंद्रों को सहयोगी बनकर अपना उगा।

अनुराग सिंह ठाकुर की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनके प्रयासों से "एक से श्रेष्ठ" का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है और वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "शिक्षित भारत" के सपने को साकार करने का एक

बच्चे इन केंद्र में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की प्रेरणा से 500 केंद्र आरम्भ किए जा चुके हैं। इन केंद्रों में कार्यरत शिक्षकों में 95 प्रतिशत से अधिक शिक्षक महिलाएं हैं।

मंत्रिमण्डल के सदस्य राजेश धर्माणी, विधायक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इसके उपरांत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में आयोजित 'विकसित भारत-2047 में युवाओं की भूमिका' संवादात्मक सत्र की अध्यक्षता करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि युवाओं को चुनौतियों से आगे देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसा माध्यम है जो युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। उन्होंने कहा कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। इस अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण, विकास की दृष्टि से तेजी से बढ़ता भारत सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों को संसद भवन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश का अच्छी तरह से उपयोग करके, हम भारत को एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं।

इस अवसर पर, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अगले 25 वर्षों का अमृत काल ही भारत को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। इस राष्ट्र को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, क्योंकि देश अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त होकर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य अब ऐसा बन चुका है कि सभी की निगाहें अब उम्मीद से भारत पर ही टिकी हैं।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चरितार्थ किया है और संसद भारत दर्शन योजना के तहत देश के असंख्य बच्चों को प्रमुख केंद्रों को देखने का अवसर मिला है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के कारण आज देश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में आयी प्राकृतिक आपदा से निपटने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी आपदा राहत के लिए कार्य किया जाना है जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राज्य को उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में उपराष्ट्रपति से सहयोग का आग्रह किया।

इससे पूर्व, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष, अभिशासक परिषद प्रो. हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया।

शिमला/शैल। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन पीटरहॉफ में किया गया। नड्डा ने कहा की नया साल राममय होगा, राम ने किया सभी मर्यादाओं का पालन। इसी प्रकार भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता भी राम की तरह मर्यादित रूप से जनता की सेवा करते हुए देश को सशक्त बनाएगा। इसी से देश शक्तिशाली होगा। नड्डा ने आह्वान किया की 22 जनवरी से हम सब सभी तीर्थ

दुनिया का मेडिकल हब बन गया है, भारत पूरे विश्व को दवाइयां भेज रहा है।

उन्होंने कहा नारी शक्ति वंदन विधेयक विधान सभा और लोक सभा में नारी की शक्ति को बढ़ायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में नारी शक्ति को शक्तियां प्रदान की गयी है तीन तलाक भी खत्म किया गया।

आज गांव, गरीब, वंचित, शोषित, युवा, किसान, महिला सभी वर्गों को बड़ा बल मिला यह। यह केवल इसलिये क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।



स्थलों और मंदिरों में सफाई अभियान चलाएंगे। राम ज्योति को नाम पर दिवाली मनाते हुए हर घर में 5 ज्योति जलाने का कार्य करेंगे।

उन्होंने कहा की राम मंदिर निर्माण में भी हिमाचल का भी बड़ा योगदान है, 11 जून 1989 को पालमपुर की पावन धरती से राम मंदिर का प्रस्ताव पारित हुआ था, आज प्रस्ताव साकार होता दिखाई दे रहा है। अटल, अडवाणी पालमपुर आये थे और इस प्रस्ताव को पारित करने का कार्य किया था यह हिमाचल के लिए गौरव की बात है।

उन्होंने कहा की कांग्रेस की गारंटी काठ की हांडी, मोदी की गारंटी सच्ची गारंटी। कांग्रेस के नेता गारंटी केवल एक बार देते हैं और पूरी नहीं करते हैं, पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं और जो नहीं कहते वह भी कर दिखाते हैं।

भाजपा का तेलंगाना में 7% से 14% मत बढ़ा और मिजोरम में दो गुना मत बढ़ा। यह सब दिखता है कि पूरे देश भर में भाजपा मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा की हिमाचल प्रदेश में भाजपा चारों सीटें जीतकर हैट्रिक लगायेगी और केंद्र में भी एक बार फिर हैट्रिक लगाते हुये देश का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बनाएंगे।

मोदी ने बदली देश की दिशा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 50 करोड़ लोगो को 5 लाख सालाना मिल रहा है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना चला कर जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आते थे उन्हें भी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करी।

नड्डा ने कहा की आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 13.5 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर आ गये हैं और अति गरीबी भारत में 1% से भी कम आ गई हैं।

भारत आज 11 से 5 पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, मोदी की गारंटी है को वर्ष 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। आज भारत

हिमाचल में 28 लाख लोगो को हिमाचल पीएम ग्राम अन्न योजना का लाभ जो रहा है, मोदी ने हिमाचल को 11000 करोड़ को हाइडल प्रोजेक्ट, 1300 करोड़ का एम्स, 5 मेडिकल कॉलेज, कैंसर सेंटर, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फोर लेन दिए हैं। हिमाचल ने आज तक कभी ऐसा काम नहीं देखा भाजपा को केंद्र सरकार ने हिमाचल को सब कुछ दिया।

उन्होंने कहा की आपदा के समय हिमाचल का दुख केंद्र ने समझा, सब देखा, सब समझा। केंद्र सरकार ने आपदा के समय हिमाचल की सब संभव सहायता की है। अभी तक केंद्र ने 1782 करोड़ आपदा के भेजा है। पर कांग्रेस ने नेता कहते हैं कुछ नहीं दिया। नड्डा ने कांग्रेस पर तज कसते हुए कहा की 'कुछ नहीं आया डालना जब में तो आना क्या'। कांग्रेस के नेताओं को बोलने से पहले सोचना चाहिए।

कांग्रेस की गारंटीयो पर मैं पूछना चाहूंगा कि जनता को इन गारंटीयो से कुछ मिला? महिलाओं को 1500 मिले? गोबर खरीदी? दूध, बिजली, कुछ मिला? उत्तर साफ है नहीं मिला।

उन्होंने कहा की यह हिमाचल की कांग्रेस सरकार बैक गियर की सरकार है, 900 संस्थान बंद, स्कूल बंद, 200 करोड़ हिम केयर के रोकें।

कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में डीजल में 7 रु और सीमेंट को 20 रु बढ़ाया। भाजपा ने घटाया पर कांग्रेस ने बढ़ाया। कांग्रेस की सरकारों का केवल यही काम है जितनी भी भाजपा की सरकारों वाले राज्य है वहां डीजल को घटाया जा रहा है।

इस आयोजन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, सिकंदर कुमार, त्रिलोक कपूर, सुखराम चौधरी, सांसद सुरेश कश्यप, सभी विधायक, मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे।



विकास की ठोस नींव पड़ चुकी है और वर्ष 2047 तक भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र होगा, जिसके लिए हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के देश भारत की ओर देखते हैं। उन्होंने कहा कि देश युवाओं से बनता है और युवाओं को अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। उन्हें अपने माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून के आगे सभी को झुकना पड़ेगा यही प्रजातांत्रिक व्यवस्था है।

उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विभिन्न सामाजिक प्रकल्पों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि 'एक से श्रेष्ठ' कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर यहां के बच्चों के स्वागत का सौभाग्य मिला। अनुराग सिंह ठाकुर से प्रभावित होकर वे भी विद्यार्थियों को अपनाने और शैक्षणिक संस्थाओं में जाने का कार्यक्रम बनाएंगे।

धनखड़ ने कहा कि एक दशक में देश में जो कार्य हुए उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अनेक पहल हुई हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि जब हम एक महिला को सशक्त करते हैं तो समाज को मजबूत करते हैं।

इस अवसर पर, उन्होंने एक से श्रेष्ठ के तहत पांच शिक्षकों को टैबलेट दिए और विद्यार्थियों को स्कूल बैग भेंट किये।

इससे पूर्व, स्कूली बच्चों ने उपराष्ट्रपति तथा उनकी धर्मपत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ को हिमाचली टोपी, शॉल व चम्बा थाल भेंटकर हिमाचली परम्परा के अनुरूप सम्मानित किया।

सार्थक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक से श्रेष्ठ, जिसका अर्थ है "सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर"। उन्होंने कहा, "इस 500वें केंद्र की यात्रा इसके मिशन-उत्थान, सशक्तिकरण और जीवन में बदलाव के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक से श्रेष्ठ का प्रभाव सिर्फ संख्याओं में नहीं मापा जाता है। यह उन व्यक्तियों की कहानियों में महसूस किया जाता है जिनके जीवन को छुआ गया है और बदल दिया गया है।"

राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने और समग्र विकास प्रदान करने की यह एक सार्थक पहल है, जो यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा की गुणवत्ता जन्मसिद्ध अधिकार बनी रहे। उन्होंने एक से श्रेष्ठ के पीछे समर्पित टीम - दूरदर्शी नेतृत्व, उत्साही स्वयंसेवकों और मेहनती कर्मचारियों को भी बधाई दी तथा कहा कि एक से श्रेष्ठ की सफलता के पीछे उनका निस्वार्थ समर्पण प्रेरक शक्ति है।

इससे पूर्व, एक से श्रेष्ठ शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने राज्यपाल को चम्बा थाल भेंट कर स्वागत किया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर उपराष्ट्रपति उनकी पत्नी डॉ.सुदेश धनखड़ तथा राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम एक ऐसा माध्यम है जो अपने केंद्रों से प्रेरणा देने का कार्य करता है। विद्यार्थियों के समग्र विकास की दिशा में यह एक अनूठी पहल है, जिसके तहत गांव और पंचायत स्तर तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 9000 से अधिक

कोर कमेटी की बैठक में शान्ता, धूमल और अनुराग का गैर हाजिर रहना पुराने संबंधों की छाया तो नहीं?

शिमला/शैल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल से राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्रियों शान्ता कुमार और प्रेम कुमार धूमल तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के न आने से भाजपा के अन्दर के हालात को लेकर अनचाहे ही जो सन्देश गया है वह कोई बहुत सुखद नहीं है। क्योंकि नड्डा के इस दौर से पहले बड़ी प्रमुखता से यह समाचार छपा था कि नड्डा प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। स्वभाविक था कि इस दौर में नड्डा के चुनाव लड़ने का सवाल मीडिया के लिये एक प्रमुख मुद्दा रहता। नड्डा ने चुनाव लड़ने से इन्कार करते हुये यह भी जोड़ दिया कि चुनाव कमेटी का निर्णय सर्वोपरि होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नड्डा के चुनाव लड़ने का फैसला अभी यथास्थिति बना हुआ है। चुनाव लड़ने की संभावना इसलिये प्रबल हो जाती है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हो जायेगा और तीसरे कार्यकाल की अनुमति भाजपा का संविधान नहीं देता। राज्यसभा में तीसरे कार्यकाल के लिये भी यही स्थिति है और अभी चुनावी राजनीति से शायद वह रिटायर होना नहीं चाहेंगे।

इस परिपेक्ष में नड्डा का यह दौरा भाजपा की चुनावी स्थितियों के आकलन के साथ ही उनके व्यक्तिगत आकलन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता के कार्यकाल में ही हुये हैं। नड्डा का गृह प्रदेश होने के नाते विधानसभा चुनावों में उनके परोक्ष/अपरोक्ष फैसलों का ही वर्चस्व रहा है। विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी सभाओं के बावजूद भी भाजपा एक प्रतिष्ठत से भी कम मतों के अन्तर से चुनाव हार गयी। पार्टी ने इन चुनावों के लिये मुख्यमंत्री भी घोषित कर रखा था। विधानसभा की हार के कारणों में नड्डा के प्रदेश में एकधिकार दखल को भी बड़ा कारण माना गया है। क्योंकि

➤ नड्डा के चुनाव लड़ने से इन्कार के साथ ही फैसला चुनाव कमेटी पर छोड़ने का अर्थ क्या है

➤ क्या भाजपा सुक्खू सरकार को अपने ऐजेंडे पर चुनाव लड़ने के लिए बाध्य कर पायेगी।

प्रदेश में कई बार नेतृत्व परिवर्तन नहीं बढ़ पायी। इस सबका परिणाम एक सार्वजनिक मंच पर हुआ की अटकलें उठी मंत्रिमण्डल में पार्टी की हार के रूप में सामने विवाद आज भी सबको याद है।



फेरबदल कुछ मंत्रियों को हटाने और विभागों में परिवर्तन की चर्चाएं चली जो अन्त में सिर्फ से आगे आया। अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर देहरा में राजीव बिन्दल को किस तरह से प्रताड़ित किया गया था वह भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है।

यह सब कुछ आज कोर कमेटी की बैठक में भाजपा के इन तीन बड़े नेताओं का न आना राजनीतिक विश्लेषकों के लिये बहुत कुछ दे गया है।

क्योंकि यदि नड्डा लोकसभा के लिये उम्मीदवार बनाये जाते हैं तो उनके लिये यह स्थिति नहीं है कि वह प्रदेश की किसी भी ओपन सीट से चुनाव लड़ने का साहस कर पायें। उनके लिये हमीरपुर ही उनकी पहली पसन्द होगी और वहां से अनुराग ठाकुर को बदलना बहुत आसान नहीं होगा। वैसे बहुत अरसे से अनुराग को चंडीगढ़ शिफ्ट करने की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में चल रही हैं। वैसे इस समय भाजपा में डॉ. बिन्दल के अतिरिक्त कोई दूसरा बड़ा नेता सुक्खू सरकार के खिलाफ ज्यादा सटीक आक्रमकता नहीं दिखा रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा लोकसभा का यह चुनाव सुक्खू सरकार को अपने ऐजेंडा पर लड़ने के लिये बाध्य कर पायेगी या स्वयं सरकार के ऐजेंडे के ट्रैप में आ जायेगी। क्योंकि इस समय सरकार और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आपस में पूरे तालमेल से चल रहा है।

मुख्य संसदीय सचिवों के प्रकरण.....पृष्ठ 1 का शेष

खड़ा होता है कि भाजपा ने जब मुख्य संसदीय सचिवों को मंत्रियों के समकक्ष मिलने वाली सुविधाओं पर रोक लगाने की मांग की है तब इस मांग से पहले इस एक्ट को निरस्त करने की मांग क्यों नहीं की? क्या इन भाजपा विधायकों को 2006 के एक्ट के प्रभाव की जानकारी नहीं थी या इसके पीछे निहित कुछ और है। इस समय जो फैसला आया है इसमें मुख्य संसदीय सचिवों का कोई अहित नहीं हुआ है। परन्तु इस फैसले पर कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों की कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आयी हैं इससे भी कुछ अलग ही संदेश जा रहा है। स्मरणीय है कि संविधान में

संशोधन करके मंत्रियों की सीमा तय करने के पीछे सरकारों की फिजूल खर्ची रोकना सबसे बड़ा उद्देश्य था और इसीलिये मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को रद्द करते हुये असम के संदर्भ में यह फैसला दिया था कि विधायिका को इस तरह का एक्ट पास करने का अधिकार ही नहीं है। असम के मामले के साथ ही हिमाचल की एसएलपी संलग्न थी। जुलाई 2017 में आये इस फैसले के कारण ही जयराम सरकार के कार्यालय में ऐसी नियुक्तियां नहीं की गयी थी। मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां 2006 के एक्ट के

तहत हुयी है और जब तक यह एक्ट निरस्त नहीं होता तब तक यह पदों पर बने भी रहेंगे। लेकिन उनके बने रहने से क्या नैतिक सवाल भी हल हो जायेगा? क्या उनके बने रहने से प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधर जायेगी? क्या सरकार को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा? यह सारे सवाल नैतिकता से जुड़े हुये हैं? इस समय सरकार ने बहुत सारी नियुक्तियां कैबिनेट रैंक में कर रखी हैं। कैबिनेट रैंक में नियुक्तियों का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट रैंक के मंत्री के समकक्ष सुविधायें मिलेंगी। भले ही ऐसी नियुक्तियों को अदालत में कोई चुनौती नहीं दी गयी है लेकिन प्रदेश जिस

तरह की वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है उसमें आने वाले दिनों में यह मुद्दे स्वतः ही चर्चा में आ जायेंगे। क्योंकि चुनाव में वायदे करते हुये मतदाताओं से यह नहीं कहा गया था कि उन्हें पूरा करने के लिये कर्ज लिया जायेगा। पिछली सरकार में जब मुख्य सचेतक और सचेतकों की नियुक्तियां की गयी थी तब उस एक्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी जो अब तक लम्बित है। अब शायद यह सरकार भी ऐसी नियुक्तियां करने जा रही है। ऐसे में जो वातावरण निर्मित होता जा रहा है उसमें सरकार पर वैधानिक सवालों की जगह नैतिक सवालों का दायरा बढ़ने जा रहा है।